नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 158
दि. 13.03.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

युद्ध की आंच से मुंबई की रसोई ठंडी, गैस संकट ने वड़ा पाव से मिड-डे मील तक सब पर डाला असर

पश्चिम एशिया में जारी तनाव और विशेष रूप से Iran–Israel conflict के चलते पैदा हुए गैस संकट का असर अब भारत के महानगरों तक साफ दिखाई देने लगा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जो अपने स्ट्रीट फूड और जीवंत खाद्य संस्कृति के लिए जानी जाती है, वहां अब रसोई की आंच धीमी पड़ती नजर आ रही है। गैस की कमी और बढ़ती लागत ने न केवल रेस्तरां और स्ट्रीट फूड कारोबारियों को संकट में डाल दिया है, बल्कि आम लोगों के रोजमर्रा के खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर भी सीधा असर पड़ा है। स्थिति यह है कि शहर में वड़ा पाव से लेकर तवा पुलाव और कटिंग चाय तक की कीमतें बढ़ गई हैं, जबकि कई लोकप्रिय खाने के स्टॉल और होटल अस्थायी रूप से बंद हो चुके हैं।

मुंबई और आसपास के इलाकों में खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि गैस की सप्लाई में आई भारी कमी के कारण शहर के लगभग 40 प्रतिशत छोटे-बड़े रेस्तरां और स्टॉल बंद हो गए हैं। यह असर खास तौर पर उन इलाकों में ज्यादा दिख रहा है, जहां स्ट्रीट फूड संस्कृति सबसे ज्यादा जीवंत मानी जाती है। Juhu Chowpatty और Dadar जैसे स्थानों पर मिलने वाले मशहूर तवा पुलाव और पाव भाजी के स्टॉल अब पहले जैसे नहीं दिखते। जहां पहले बड़े तवे पर घंटों धीमी आंच पर भाजी पकती थी और उसकी खुशबू दूर-दूर तक फैलती थी, वहीं

अब गैस बचाने के लिए पकाने का समय कम कर दिया गया है। इसका सीधा असर स्वाद पर पड़ा है और कई ग्राहकों का कहना है कि पहले जैसा सोंधापन अब नहीं मिल रहा।

गैस संकट का सबसे बड़ा असर आम मुम्बईकर की लाइफलाइन माने जाने वाले वड़ा पाव पर पड़ा है। शहर के कई इलाकों में इसकी कीमतों में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। Parel और Girgaon जैसे क्षेत्रों में जहां पहले वड़ा पाव 15 से 20 रुपये में मिल जाता था, अब वही 25 से 30 रुपये तक पहुंच गया है। दुकानदारों का कहना है कि वड़ा तलने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस की उपलब्धता कम हो गई है और सिलेंडर की कीमत भी बढ़ गई है, जिससे उन्हें मजबूरी में दाम बढ़ाने पड़े हैं।

इसी तरह ऑफिस जाने वाले लोगों की सुबह की आदत बन चुकी कटिंग चाय भी महंगी हो गई है। पहले 10 रुपये में मिलने वाली चाय अब 15 रुपये तक पहुंच गई है। शहर के कई हिस्सों में तवा रोटी की कीमत भी बढ़ गई है। Andheri और Borivali की खाऊ गलियों में पहले 10 से 12 रुपये में मिलने वाली रोटी अब 18 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसका सीधा असर मध्यम वर्ग और रोज कमाने-खाने वाले लोगों के बजट पर पड़ा है।

गैस संकट ने केवल स्ट्रीट फूड तक ही असर सीमित नहीं रखा है, बल्कि बड़े ढाबों और रेस्तरां के मेनू भी बदलने लगे हैं। Navi Mumbai के पाम बीच रोड और Thane के घोड़बंदर रोड पर स्थित कई ढाबों ने अपने मेनू से तंदूरी चिकन और रेशमी कबाब जैसे व्यंजन अस्थायी रूप से हटा दिए हैं। इन व्यंजनों को पकाने में ज्यादा समय और गैस की जरूरत होती है, इसलिए होटल मालिक फिलहाल उन्हीं डिशों पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें कम समय में तैयार किया जा सकता है। इस संकट का असर शहर की पारंपरिक डिशों पर भी दिख रहा है। ठाणे और आसपास के इलाकों में मशहूर मिसाल-पाव की दुकानों पर ग्राहकों को अब लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मिसाल के साथ मिलने वाला रस्सा या कट बनाने के लिए लगातार उबाल जरूरी होता है, लेकिन गैस की कमी के कारण कई दुकानदार सीमित मात्रा में ही इसे तैयार कर पा रहे हैं।

गैस की कमी ने शहर में पुराने समय के चूल्हों और वैकल्पिक तकनीकों की वापसी भी करवा दी है। Bandra Kurla Complex और Nariman Point के कई प्रीमियम रेस्तरां अब गैस की निर्भरता कम करने के लिए इंडक्शन प्लेट और एयर फ्रायर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। वहीं Mohammed Ali Road इलाके में इलेक्ट्रिक स्टोव, लकड़ी के चूल्हे और कोयले की मांग अचानक बढ़ गई है। कुछ छोटे होटल तो मजबूरी में लकड़ी के चूल्हों पर खाना पकाने लगे हैं, जिससे लोगों को पुराने दौर की यादें ताजा हो रही हैं।

इस संकट का सबसे गंभीर असर स्कूलों में चलने वाली पोषण योजनाओं पर भी पड़ा है। मुंबई में करीब सात लाख विद्यार्थियों को मिलने वाला भोजन प्रभावित हो गया है। सरकार की PM Poshan Scheme के तहत मिलने वाला मिड-डे मील गैस की कमी के कारण कई स्कूलों में बंद करना पड़ा है। इससे हजारों गरीब बच्चों के दैनिक पोषण पर सीधा असर पड़ा है।

कन्नूर की राजनीतिक हिंसा पर हाईकोर्ट का सख्त संदेश, याकूब हत्याकांड में पांच भाजपा कार्यकर्ताओं की उम्रकैद बरकरार

Kannur। केरल के कन्नूर जिले में लगभग दो दशक पहले हुए एक बहुचर्चित राजनीतिक हत्याकांड पर बड़ा न्यायिक फैसला सामने आया है। Kerala High Court ने वर्ष 2006 में माकपा कार्यकर्ता याकूब की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए पांच भाजपा कार्यकर्ताओं की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि राजनीतिक प्रतिशोध के नाम पर हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकती। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और चिकित्सा रिपोर्ट इतने मजबूत हैं कि दोषियों को दी गई सजा में किसी प्रकार की राहत देने का कोई आधार नहीं बनता।

यह फैसला न्यायमूर्ति A. K. Jayasankaran Nambiar और न्यायमूर्ति Jobin Sebastian की खंडपीठ ने सुनाया। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान निचली अदालत के फैसले और उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण किया और अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि दोषियों के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह प्रमाणित होते हैं। इसलिए उन्हें दी गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखना ही न्यायसंगत होगा।

यह मामला वर्ष 2006 में कन्नूर जिले में हुई एक सनसनीखेज घटना से जुड़ा है, जिसमें 24 वर्षीय युवक याकूब की बम हमले में हत्या कर दी गई थी। याकूब स्थानीय स्तर पर Communist Party of India (Marxist) से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था। घटना उस समय हुई जब जिले में राजनीतिक तनाव अपने चरम पर था और विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच टकराव की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं।

अदालत ने अपने फैसले में इस तथ्य को भी रेखांकित किया कि यह हत्या अचानक हुई हिंसा का परिणाम नहीं थी, बल्कि प्रतिशोध की भावना से की गई एक सुनियोजित कार्रवाई थी। अदालत के अनुसार घटना से कुछ दिन पहले एक Bharatiya Janata Party कार्यकर्ता पर हमला हुआ था, जिसके बाद कथित तौर पर बदले की भावना में याकूब को निशाना बनाया गया। आरोपियों ने उस पर बम से हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।

खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कन्नूर जिले में लंबे समय से वामपंथी दलों और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती रही है। इस प्रतिस्पर्धा ने कई बार हिंसक रूप लिया है और अनेक युवाओं की जान चली गई है। अदालत ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हिंसा के जरिए उन्हें व्यक्त करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

इस मामले में जिन पांच लोगों की सजा को अदालत ने बरकरार रखा है, उनमें विजयेश (43), प्रकाशन (48), काव्येश (43), मनोहरन (31) और शंकरन मास्टर (49) शामिल हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इन सभी के खिलाफ जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, वे स्पष्ट रूप से उनकी संलिप्तता को साबित करते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटना के तुरंत बाद इन लोगों की पहचान हमलावरों के रूप में की थी और उनकी गवाही में कोई गंभीर विरोधाभास नहीं पाया गया।

अदालत ने यह भी कहा कि मामले की जांच के दौरान एकत्र किए गए भौतिक साक्ष्य और चिकित्सा रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष के दावों की पुष्टि करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि विस्फोट के कारण याकूब के सिर में अत्यंत गंभीर चोट आई थी। रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में उसका मस्तिष्क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जो उसकी मौत का मुख्य कारण बना। इस प्रकार चिकित्सा प्रमाण भी स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि हमला अत्यंत क्रूर और घातक था।

निचली अदालत ने पहले ही इस मामले में दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील की थी। अपील में आरोपियों की ओर से साक्ष्यों पर सवाल उठाए गए और सजा में राहत की मांग की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने विस्तृत सुनवाई के बाद पाया कि निचली अदालत का निर्णय तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर सही है और उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

कन्नूर जिला लंबे समय से राजनीतिक हिंसा की घटनाओं के लिए चर्चा में रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच टकराव और हमलों की कई घटनाएं यहां पहले भी सामने आ चुकी हैं। इन घटनाओं ने अक्सर राज्य की राजनीति और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय हैं और इन्हें रोकने के लिए समाज और राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी से काम करना होगा।

इस फैसले को कई कानूनी विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि इससे यह स्पष्ट संदेश गया है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के नाम पर की गई हिंसा को न्यायपालिका किसी भी स्थिति में सहन नहीं करेगी। अदालत का यह भी मानना है कि कानून का शासन तभी मजबूत रहेगा जब दोषियों को उनके अपराध के अनुरूप सजा मिले और न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से आगे बढ़े।

फिलहाल इस फैसले के बाद एक बार फिर कन्नूर की राजनीतिक हिंसा का मुद्दा चर्चा में आ गया है। कई लोगों का मानना है कि यह निर्णय न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय का एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज को यह याद दिलाने वाला भी है कि लोकतंत्र में मतभेदों का समाधान हिंसा नहीं बल्कि संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से ही होना चाहिए।

जेकेसीए घोटाले में फारूक अब्दुल्ला पर कानूनी शिकंजा, श्रीनगर कोर्ट से गैर-जमानती वारंट जारी

Srinagar / Jammu। जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और Jammu & Kashmir National Conference के अध्यक्ष Farooq Abdullah के खिलाफ अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। यह कार्रवाई जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ से जुड़े बहुचर्चित वित्तीय घोटाले के मामले में की गई है, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी द्वारा लंबे समय से की जा रही है। अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि यह मामला राज्य की राजनीति से जुड़े एक बड़े नाम से संबंधित है।

जानकारी के अनुसार श्रीनगर की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को यह आदेश उस समय दिया जब मामले की सुनवाई के दौरान फारूक अब्दुल्ला अदालत के सामने पेश नहीं हुए। अदालत ने इस मामले में जांच कर रही Central Bureau of Investigation की ओर से प्रस्तुत तथ्यों और केस की प्रगति को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया। अदालत का मानना था कि आरोपी की अनुपस्थिति में कार्यवाही को आगे बढ़ाना संभव नहीं है, इसलिए उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी करना जरूरी हो गया। यह पूरा मामला Jammu and Kashmir Cricket Association से जुड़े कथित वित्तीय घोटाले से संबंधित है। आरोप है कि क्रिकेट संघ को खेल गतिविधियों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो धनराशि मिली थी, उसका इस्तेमाल नियमों के अनुरूप नहीं किया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार इस दौरान करोड़ों रुपये के फंड में अनियमितताएं हुईं और कई संदिग्ध लेन-देन सामने आए।

फारूक अब्दुल्ला वर्ष 2001 से 2011 के बीच जम्मू-कश्मीर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहे थे। इसी अवधि के दौरान संघ के वित्तीय लेन-देन को लेकर सवाल उठे थे। यह विवाद वर्ष 2012 में उस समय सामने आया जब संघ के तत्कालीन कोषाध्यक्ष Manzoor Wazir ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में संघ के उस समय के महासचिव Mohammad Saleem Khan और पूर्व कोषाध्यक्ष Ahsan Mirza पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। इस शिकायत के बाद मामले ने तूल पकड़ा और जांच की मांग तेज हो गई।

जांच के दौरान यह आरोप सामने आया कि क्रिकेट के विकास के लिए जारी किए गए करोड़ों रुपये के फंड का सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ। यह राशि मुख्य रूप से Board of Control for Cricket in India द्वारा जम्मू-कश्मीर में क्रिकेट के ढांचे को मजबूत करने के लिए दी गई थी। रिपोर्टों के अनुसार बीसीसीआई ने इस क्षेत्र में क्रिकेट गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की ग्रांट दी थी, जिसमें से लगभग 43 करोड़ रुपये के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठे।

जांच एजेंसियों का दावा है कि इन फंडों का एक हिस्सा कथित तौर पर फर्जी लेन-देन और धोखाधड़ी के जरिए निकाला गया। आरोप है कि संघ के खातों से कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन किए गए और धनराशि को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसी आधार पर वर्ष 2018 में सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें फारूक अब्दुल्ला सहित संघ के कई पूर्व अधिकारियों के नाम शामिल किए गए थे।

इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी वर्ष 2015 में Jammu and Kashmir High Court ने सीबीआई को सौंप दी थी। अदालत ने उस समय माना था कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी की भूमिका जरूरी है। इसके बाद से ही यह केस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से गुजर रहा है।

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि फारूक अब्दुल्ला व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए। बताया गया कि उस समय वे जम्मू में मौजूद थे। उनके वकील ने अदालत में यह दलील दी कि कुछ कारणों से वह व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सके, इसलिए उन्हें पेशी से छूट दी जाए। हालांकि अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि बचाव पक्ष को वर्चुअल माध्यम से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का विकल्प दिया गया था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया।

अदालत ने इस स्थिति को गंभीर मानते हुए उनकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत ने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को की जाएगी, जिसमें आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

दूसरी ओर फारूक अब्दुल्ला पहले भी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर चुके हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी नहीं की और यह मामला राजनीतिक कारणों से उछाला गया है। उनका यह भी दावा रहा है कि जांच और अदालत की प्रक्रिया में सच्चाई सामने आ जाएगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर की राजनीति के सबसे वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उनके परिवार का राज्य की राजनीति में कई दशकों से महत्वपूर्ण स्थान रहा है और वे कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।

गिरनार अंबाजी मंदिर विवाद: वायरल वीडियो के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 11 पुजारी और सहायकों को हटाया

Junagadh। गुजरात के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले गिरनार पर्वत पर स्थित प्रसिद्ध Girnar Ambaji Temple में कथित तौर पर मांसाहारी भोजन और शराब के सेवन का वीडियो वायरल होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद धार्मिक भावनाओं को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं और प्रशासन को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मंदिर से जुड़े 11 पुजारियों और सहायकों को उनके पदों से हटा दिया है और पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए हैं।

प्रशासन के अनुसार वायरल वीडियो सामने आने के बाद मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। बताया जा रहा है कि वीडियो में कुछ लोग मंदिर परिसर के भीतर कथित रूप से मांसाहारी भोजन करते और शराब पीते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि वीडियो में दिखाई दे रही गतिविधियां वास्तव में मंदिर परिसर के अंदर हुई थीं या नहीं।

जूनागढ़ के जिला कलेक्टर Anil Ranavasiya ने बताया कि मामले की प्रारंभिक जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मंदिर से जुड़े 11 कर्मचारियों को उनके दायित्वों से हटा दिया है। इन कर्मचारियों में मंदिर के पुजारी और उनके सहायक शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने तक इन सभी को हटाना जरूरी था ताकि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित

की जा सके और मंदिर की व्यवस्था प्रभावित न हो।

कलेक्टर ने यह भी बताया कि मंदिर में पूजा-पाठ की नियमित व्यवस्था बनाए रखने के लिए फिलहाल तीन नए पुजारियों की अस्थायी नियुक्ति की गई है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मंदिर की दैनिक पूजा और अन्य धार्मिक गतिविधियां बिना किसी बाधा के जारी रहें।

मामले की जांच के लिए प्रशासन ने विस्तृत प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है और Junagadh Sub-Divisional Magistrate Office इस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रहा है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वायरल वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था, उसमें दिखाई दे रहे लोग कौन हैं और क्या वास्तव में मंदिर परिसर के भीतर प्रतिबंधित गतिविधियां हुई थीं।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार कई मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि गिरनार पहाड़ी पर स्थित मंदिर परिसर में कुछ व्यक्तियों ने मांसाहारी भोजन किया और शराब का सेवन किया। चूंकि मंदिर को एक पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है, इसलिए इस तरह की गतिविधियों के आरोपों ने लोगों की भावनाओं को झकझोर दिया है। इसी कारण प्रशासन ने बिना देर किए जांच शुरू कर दी है ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके।

इस घटना ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी प्रतिक्रिया पैदा की है। स्थानीय विधायक Sanjay Koradia ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि यदि मंदिर परिसर में इस तरह की घटना हुई है तो यह सनातन धर्म की आस्था का अपमान है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। विधायक ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से बातचीत कर मामले की पूरी जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है।

उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात की सरकार और समाज दोनों ही सनातन परंपराओं और धार्मिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं, इसलिए इस तरह की घटनाओं को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर धार्मिक स्थलों की गरिमा को ठेस पहुंचाने और सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

गिरनार पर्वत और वहां स्थित अंबाजी मंदिर गुजरात के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिने जाते हैं। हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं। विशेष रूप से नवरात्रि और अन्य धार्मिक अवसरों पर यहां भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में मंदिर परिसर से जुड़ी किसी भी विवादित घटना को लेकर लोगों की संवेदनाएं स्वाभाविक रूप से गहरी हो जाती हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया के दौर में किसी भी वीडियो या सूचना के वायरल होने से पहले उसकी सत्यता की जांच बेहद आवश्यक है, क्योंकि कई बार अधूरी या भ्रामक जानकारी भी बड़े विवाद का कारण बन जाती है। इसी कारण प्रशासन ने इस मामले में सावधानी बरतते हुए यह स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा।

फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता मंदिर की पवित्रता और व्यवस्था बनाए रखना है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी हो ताकि सच्चाई सामने आ सके और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। अब पूरे मामले पर लोगों की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट होगा कि वायरल वीडियो में दिखाई देने वाली घटनाएं वास्तव में क्या थीं और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है।

संपादकीय

दूषित पानी शुद्ध करने की संवेदनशील पहल हो

अक्सर कहा जाता है कि जल ही जीवन है। लेकिन यह जल यदि दूषित हो तो क्या इसे जीवन कहा जा सकता है? यूं तो देश के गांवों में महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन जोर-शोर से चलाया जाता रहा है। लेकिन यह बात परेशान करती है कि पेयजल का बड़ा हिस्सा प्रदूषित पाया गया है। लोग सेहत के लिये हानिकारक जल पीने को मजबूर हैं। फलतः इससे उत्पन्न बीमारियों की चुनौतियों का सामना करने को बाध्य होते हैं। यह हमारे नीति-नियंताओं की विफलता ही कही जाएगी कि देश के करोड़ों लोग आज भी स्वच्छ जल की उपलब्धता से वंचित हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि देश के तमाम इलाकों में लिए गए दूषित पेयजल नमूनों के करीब दो तिहाई हिस्से को शुद्ध करने के प्रयास नहीं हुए हैं। जो इस बात को दर्शाता है कि आज भी देश के करोड़ों लोग स्वच्छ पेयजल हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति हमारे विकास के मॉडल व तरक्की के दावों की तार्किकता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। यही वजह है कि दूषित जल से होने वाले रोगों का दायरा बढ़ रहा है। यह अच्छी बात है कि जोर-शोर से घर-घर नल से जल पहुंचाने की सार्थक पहल की गई। निस्संदेह, हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसे अपने घर में स्वच्छ पेयजल मिले। इसी मकसद से साल 2019 में जल जीवन मिशन को सिरे चढ़ाया गया था। लेकिन इस योजना के सुरक्षित तरीके से संचालन और स्वच्छ जल आपूर्ति को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। यह हकीकत है कि जब लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिलता तो कई तरह के रोगों के पैदा होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। कहा भी जाता है कि हमारे अधिकांश रोग पेट से ही शुरू होते हैं। खासकर बच्चों व बुजुर्गों के लिये यह एक बेहद संवेदनशील मामला है। जिससे बचने के लिये स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो जाता है।

देश में बार-बार स्वच्छ शहर का खिताब हासिल करने वाले मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में पिछले दिनों प्रदूषित पेयजल से होने वाली मौतों ने देश में खतरे की घंटी बजायी। घटना ने स्पष्ट संकेत दिया कि यदि इस दिशा में व्यापक स्तर पर प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले समय में देश के सामने गंभीर स्वास्थ्य चुनौती पैदा हो सकती है। उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीणों तक पहुंचाए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की परख के लिये पानी के सैंपल लिए जाते हैं। साथ ही स्वच्छ पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। यहां उल्लेखनीय है कि बीते साल जल जीवन मिशन के तहत तमाम राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में पेयजल सैंपलों की जांच की गई। लेकिन चिंताजनक स्थिति यह है कि कुल नमूनों के छब्बीस प्रतिशत को ही शुद्ध करने के प्रयास हुए हैं। आखिर देश के किसी भी भाग में पेयजल के सैंपल लेने का क्या औचित्य रह जाता है, जब प्रदूषित जल को लेकर उपचारात्मक प्रयास न किए जाएं। सवाल केवल ग्रामीण इलाकों के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का ही नहीं है, शहरी इलाकों में शुद्ध जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। गाहे-बगाहे देश के शहरी इलाकों में भी प्रदूषित जल पीने से बीमार होने की खबरें आती रहती हैं। लेकिन स्थानीय निकाय इस चुनौती को गंभीरता से नहीं लेते। संपन्न लोग तो आरओ तथा फिल्टर आदि वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन कमजोर वर्ग व सामान्य लोग दूषित पानी के उपयोग के लिये मजबूर होते हैं। स्वच्छ जल प्राप्त करना हर नागरिक का मौलिक व जीवन रक्षा का अधिकार जैसा है, जिसे गंभीरता से लेना चाहिए। इंदौर की घटना से सबक लेकर स्थानीय निकायों और प्रशासन को पेयजल व सीवर लाइन को सुरक्षित दूरी पर रखना सुनिश्चित करना चाहिए। जिन इलाकों में पेयजल पाइप लाइन को बिछे दशकों हो गए हैं, वहां उन्हें बदलने का काम युद्धस्तर पर किया जाना चाहिए। साथ ही रोजमर्रा की जरूरतों में काम आने वाले भूजल की गुणवत्ता सुधारने तथा घातक रसायनों से उसे मुक्त कराने की दिशा में गंभीर पहल की जाए।

उत्तराखंड की राजधानी का अनसुलझा विवाद

"राजधानी केवल ईंट-पत्थर की इमारतों या विधानसभा की सीढ़ियों का नाम नहीं होती; यह राज्य के 'विजन' और उसकी 'आत्मा' का प्रतिबिंब होती है। 25 साल बाद भी उत्तराखंड की सरकारें 'ग्रीष्मकालीन' और 'शीतकालीन' के जुमलों में उलझी हैं।

चमोली जिले में स्थित भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में जब भी दो-तीन दिनों के लिए उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आयोजित होता है तो सीमांत हिमालयी प्रदेश उत्तराखंड की स्थाई राजधानी का मुद्दा फिर गर्मा जाता है। नवम्बर, 2000 से लेकर अब तक राज्य गठन के 25 साल हो चुके हैं, लेकिन राज्य की राजधानी का मुद्दा अब तक नहीं सुलझा है।

भाजपा की सरकार ने राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिए भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित तो कर दिया, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल तो दूर, यह घोषणा राज्य की राजधानी की मांग को लेकर एक अभूतपूर्व आंदोलन चलाने वाले लोगों के गले भी नहीं उतरी। किसी एक स्थान पर महज कुछ दिनों के लिए विधानसभा सत्र आयोजित करने से वह स्थान राजधानी नहीं बन जाता! अगर लोग भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी मान भी लें, तो शीतकालीन या स्थाई राजधानी का सवाल अभी भी अनुत्तरित है। जिस भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है, वहां पिछले छह वर्षों में केवल एक बार ग्रीष्मकालीन सत्र हुआ, और वह भी बहुत संक्षिप्त।

उत्तराखंड अकेला राज्य है, जिसकी राजधानी आज तक तय नहीं हो पाई। इसके लिए उत्तराखंड का अपना राजनीतिक तंत्र जिम्मेदार रहा है, जो राज्य गठन से लेकर अब तक राजधानी को लेकर एक राय नहीं बना सका। जब संसद में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पास हो गया था, तो उसी समय से राजधानी की तलाश शुरू हो गई थी। उस समय जब विधायकों और सांसदों के बीच राजधानी को लेकर गढ़वाल और कुमाऊं के बीच रस्साकशी होने लगी, तो तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने यह मुद्दा उत्तराखंड के लोगों पर छोड़ दिया और तात्कालिक ढांचागत सुविधाओं को देखते हुए देहरादून को अस्थायी राजधानी घोषित किया। साथ ही कुमाऊं के लोगों को संतुष्ट करने के लिए नैनीताल को हाईकोर्ट दे दिया। आज ये दोनों शहर अपनी सीमित धारण क्षमता के कारण राजधानी और हाईकोर्ट के बोझ तले दबे हुए हैं। दोनों ही भूगर्भीय दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। नैनीताल की विकट स्थिति को देखते हुए स्वयं हाईकोर्ट को अपने लिए कोई नई जगह तलाशने के आदेश देने पड़े।

केंद्र सरकार ने राजधानी के चयन की जिम्मेदारी उत्तराखंड (उत्तरांचल) सरकार पर छोड़ दी थी, इसलिए पहली नित्यानंद स्वामी सरकार ने इसके लिए दीक्षित आयोग का गठन कर दिया, जिसे छह माह के अंदर अपनी सिफारिशें देनी थीं। लेकिन आयोग उत्तराखंड की राजनीति से अपरिचित नहीं था, इसलिए उसने मामला आठ साल तक लटकाए रखा। फिर भी दीक्षित आयोग कायम रहा। 11 जनवरी, 2001 को गठित इस आयोग ने भारी जन दबाव के बाद 17 अगस्त, 2008 को अपनी रिपोर्ट दाखिल की, जो दिसंबर, 2008 में विधानसभा में रखी गई। दीक्षित आयोग की यह रिपोर्ट भी उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति की पोल खोलने के लिए काफी है। आयोग के समक्ष 70 विधायकों में से केवल एक और पांच सांसदों में से भी एक ने अपनी राय दी।

सर्वेक्षणों में जनता का बहुमत गैरसैंण के पक्ष में था, लेकिन आयोग के सामने लिखित राय देने वाले केवल 4-5 लोग ही इसके पक्ष में खड़े दिखे। आयोग में राय देने वाले अधिकांश लोगों ने अपने क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता दी। गढ़वाल के लोगों ने ऋषिकेश या देहरादून और कुमाऊं के लोगों ने रामनगर या काशीपुर को वरीयता दी। ऐसी स्थिति में आयोग ने देहरादून के रायपुर क्षेत्र को ही अपनी वरीयता दे दी।

भराड़ीसैंण में आयोजित बजट सत्र के दौरान 4 मार्च, 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हो गई। इस घोषणा की पुष्टि के लिए 8 जून, 2020 को आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई। भराड़ीसैंण के 'ग्रीष्मकालीन राजधानी' बनने के बाद पिछले छह वर्षों में केवल जून, 2022 में ही वहां वास्तविक ग्रीष्मकालीन सत्र हुआ। एक-दो सत्र शीतकाल में भी हुए, लेकिन वे आधे-अधूरे ही थे! एक सप्ताह तक विधानसभा चलाना राजधानी चलाना नहीं होता। संक्षिप्त सत्र पर ही करोड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं और जनता से लेकर कर्मचारियों तक को होने वाली असुविधा अलग होती है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, उत्तराखंड में 25 वर्षों के दौरान 80 हजार करोड़ का कर्ज चढ़ चुका है।

यह केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे लंबा 'राजनीतिक छलावा' है। अगर भराड़ीसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी मान लिया, तो शीतकालीन राजधानी कहां है? इसका उत्तर भी गुम हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल जैसे दल भराड़ीसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि, कांग्रेस दो बार सत्ता में रह चुकी है और उत्तराखंड क्रांति दल भी सरकारों में शामिल रहा है। ऐसी स्थिति में देहरादून को स्थायी या शीतकालीन राजधानी घोषित करना राजनीतिक दृष्टि से जोखिम से खाली नहीं है। राजधानी केवल ईंट-पत्थर की इमारतों या विधानसभा की सीढ़ियों का नाम नहीं होती; यह राज्य के 'विजन' और उसकी 'आत्मा' का प्रतिबिंब होती है। 25 साल बाद भी यदि उत्तराखंड की सरकारें 'ग्रीष्मकालीन' और 'शीतकालीन' के जुमलों में उलझी हैं तो यह उन शहीदों के बलिदान का अपमान है जिन्होंने एक समृद्ध और स्वाभिमानी पहाड़ के लिए अपना रक्त दिया था।

यदि भराड़ीसैंण को राजधानी बनाना है तो वहां केवल सत्र नहीं, बल्कि 'शासन' होना चाहिए। यदि देहरादून ही स्थायी ठिकाना है तो फिर 'अस्थाई' का ढोंग बंद कर पहाड़ों के विकास के लिए कोई वैकल्पिक मॉडल पेश किया जाना चाहिए।

प्रेरणा

सत्य की कीमत: चेचन्या की पीड़ा को दुनिया तक पहुंचाने वाली अन्ना पोलिटकोव्स्काया की साहसिक यात्रा

बीसवीं सदी के अंतिम वर्षों में दुनिया के कई हिस्सों में राजनीतिक संघर्ष और अस्थिरता बढ़ रही थी। इसी दौर में रूस के दक्षिणी हिस्से में स्थित चेचन्या क्षेत्र एक लंबे और हिंसक संघर्ष का केंद्र बन गया था। यह संघर्ष केवल हथियारों और राजनीतिक सत्ता का मामला नहीं था, बल्कि इसके बीच हजारों निर्दोष नागरिकों की जिंदगी भी उलझ गई थी। गांवों में डर का माहौल था, रातों में गोलियों की आवाजें सुनाई देती थीं और कई परिवार अचानक अपने प्रियजनों के गायब हो जाने की पीड़ा झेल रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश लोग इस क्षेत्र से दूर रहना ही सुरक्षित समझते थे, लेकिन एक पत्रकार ने तय किया कि वह इस संघर्ष की सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगी। वह पत्रकार थीं Anna Politkovskaya, जिन्होंने अपने साहस और प्रतिबद्धता से पत्रकारिता को केवल पेशा नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत किया।

उस समय चेचन्या का नाम सुनते ही लोगों के मन में भय की भावना पैदा हो जाती थी। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी वहां की खबरें सीमित और अक्सर आधिकारिक बयानों पर आधारित होती थीं। लेकिन जमीन पर रहने वाले लोगों की वास्तविक पीड़ा इन खबरों में दिखाई नहीं देती थी। अन्ना पोलिटकोव्स्काया ने महसूस किया कि यदि कोई पत्रकार वहां जाकर लोगों की कहानियां नहीं सुनेगा, तो दुनिया कभी भी उस मानवीय त्रासदी को पूरी तरह नहीं समझ पाएगी। इसी विचार के साथ उन्होंने कई बार चेचन्या की यात्रा की और वहां के गांवों, कस्बों तथा शरणार्थी शिविरों में जाकर लोगों से बातचीत की।

उनकी रिपोर्टिंग का तरीका बहुत अलग था। वे केवल घटनाओं की जानकारी इकट्ठा करने तक सीमित नहीं रहती थीं, बल्कि वे लोगों के जीवन को समझने की कोशिश करती थीं। कई बार वे छोटे-छोटे घरों में बैठकर घंटों तक उन परिवारों की कहानियां सुनती थीं जिनके सदस्य अचानक गायब हो गए थे। कई महिलाओं ने उन्हें बताया कि कैसे उनके पति या बेटे को सुरक्षा बलों द्वारा पूछताछ के लिए ले जाया गया और उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्हें कई जगहों पर अपने प्रियजनों की तलाश करनी पड़ी, लेकिन हर जगह उन्हें केवल निराशा ही मिली।

अन्ना इन कहानियों को केवल व्यक्तिगत दुख के रूप में नहीं देखती थीं, बल्कि उन्हें एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक संकट के संकेत के रूप में समझती थीं। उन्होंने इन अनुभवों को विस्तार से अपने लेखों में लिखा और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में प्रकाशित कराया। उनके लेखों में आंकड़ों से अधिक मानवीय अनुभवों का महत्व होता था। वे यह दिखाने की कोशिश करती थीं कि युद्ध और हिंसा का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ता है जो किसी भी पक्ष के साथ सीधे तौर पर जुड़े नहीं होते।

उनकी रिपोर्टिंग के कारण धीरे-धीरे चेचन्या की स्थिति पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान बढ़ने लगा। मानवाधिकार संगठनों ने वहां की घटनाओं पर सवाल उठाने शुरू किए और कई देशों के पत्रकार भी इस मुद्दे को गंभीरता से देखने लगे। अन्ना पोलिटकोव्स्काया ने यह साबित किया कि सच्ची पत्रकारिता केवल सूचना देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज के उन पहलुओं को उजागर करने का भी माध्यम है जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

हालांकि इस साहसिक काम की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। उनके लेखों से कई शक्तिशाली लोगों को असुविधा होने लगी थी। उन्हें बार-बार धमकियां मिलती थीं और कई बार उन्हें चेतावनी दी गई कि वे इस विषय पर लिखना बंद कर दें। लेकिन अन्ना का मानना था कि यदि पत्रकार डरकर चुप हो जाए, तो समाज में अन्याय को उजागर करने वाला कोई नहीं बचेगा। वे अक्सर कहती थीं कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता।

उनकी पत्रकारिता की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे हमेशा मानवता के दृष्टिकोण से सोचती थीं। वे यह समझती थीं कि युद्ध और संघर्ष की कहानियां केवल राजनीति या रणनीति तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि वे हजारों परिवारों की भावनाओं और उम्मीदों से भी जुड़ी होती हैं। उनके लेखों में बच्चों के डर, माताओं के आँसू और बुजुर्गों की बेबसी की झलक मिलती थी। यही वजह थी कि उनके लेख पाठकों के दिलों को गहराई से प्रभावित करते थे।

समय के साथ अन्ना पोलिटकोव्स्काया का नाम निडर पत्रकारिता का प्रतीक बन गया। दुनिया भर में उनके काम की सराहना होने लगी और कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उनके प्रयासों को सम्मानित किया गया। लेकिन उनके लिए यह सम्मान या प्रसिद्धि कभी भी प्राथमिक लक्ष्य नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य था कि दुनिया चेचन्या के लोगों की पीड़ा को समझे और वहां हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए।

उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि पत्रकारिता का असली अर्थ केवल समाचार देना नहीं है। यह एक ऐसा माध्यम है जो समाज में न्याय, संवेदना और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत कर सकता है। जब एक पत्रकार ईमानदारी और साहस के साथ काम करता है, तो उसकी कलम केवल शब्द नहीं लिखती बल्कि इतिहास को भी दर्ज करती है।

आज जब दुनिया में सूचना के कई माध्यम मौजूद हैं, तब भी सच्ची और जिम्मेदार पत्रकारिता की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस की जाती है। अन्ना पोलिटकोव्स्काया का जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक व्यक्ति की ईमानदार कोशिश भी दुनिया का ध्यान किसी महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर खींच सकती है। उन्होंने यह दिखाया कि पत्रकार का कर्तव्य केवल घटनाओं को दर्ज करना नहीं, बल्कि उन आवाजों को सामने लाना भी है जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है।

उनकी विरासत आज भी पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को प्रेरित करती है। उनकी कहानी यह याद दिलाती है कि सच के रास्ते पर चलना कठिन जरूर होता है, लेकिन यही रास्ता समाज को अधिक न्यायपूर्ण और संवेदनशील बनाता है। अन्ना पोलिटकोव्स्काया ने अपने साहस और समर्पण से यह सिद्ध किया कि जब कोई व्यक्ति सत्य और मानवता के लिए खड़ा होता है, तो उसकी आवाज सीमाओं और समय की बाधाओं को पार कर लोगों तक पहुंचती रहती है।

इस तरह उनकी जीवन यात्रा केवल एक पत्रकार की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास की कहानी भी है कि सत्य और न्याय के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। अन्ना पोलिटकोव्स्काया ने अपने लेखन से यह संदेश दिया कि अगर समाज में अन्याय हो रहा हो, तो चुप रहना सबसे बड़ी गलती होती है। उनकी कलम ने यह साबित किया कि एक साहसी पत्रकार केवल खबरें नहीं लिखता, बल्कि वह उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण भी बन सकता है जिनकी आवाज अक्सर दुनिया तक नहीं पहुंच पाती।

Trump के 'फ्रेंडली टेकओवर' प्लान ने दुनियाभर में मचाया हड़कंप! वेनेजुएला-ईरान के बाद अब इस देश से अमेरिका करेगा 64 साल पुराना हिसाब बराबर

मिडिल ईस्ट के युद्ध का आज तेरहवां दिन है। लेकिन 2026 ऐसा साल बन चुका है जहाँ एक संकट खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने खड़ा मिल जाता है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अगला मोर्चा क्यूबा बनने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। ट्रंप इसे "फ्रेंडली टेकओवर" यानी शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन बता रहे हैं। लेकिन जमीन पर जो हालात बन रहे हैं, वो किसी भी तरह से शांतिपूर्ण नहीं दिखते। जनवरी से अमेरिका ने क्यूबा पर जो आर्थिक घेराबंदी शुरू की है, उसका असर अब साफ दिखने लगा है। पिछले महीने एक चौंकाने वाली बात सामने आई। क्यूबा को एक भी बैरल तेल नहीं मिला। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कई हवाई जहाज़ क्यूबा में उतरने से बच रहे हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें वापस उड़ान भरने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं मिल रहा। अस्पतालों ने भी मजबूरी में गैर-जरूरी ऑपरेशन और इलाज रोक दिए हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भी है। पिछले 50 सालों से बार-बार कहा गया कि क्यूबा की सरकार गिरने वाली है, लेकिन हर बार यह भविष्यवाणी गलत साबित हुई। अब जब अमेरिका पहले से ही मिडिल ईस्ट के युद्ध में उलझा हुआ है, तो क्या वाकई वह क्यूबा में नया सैन्य मोर्चा खोल सकता है? आज हम अमेरिका और क्यूबा के रिश्तों का एमआरआई स्कैन करेंगे। ये कब बिगड़ने शुरू हुए, क्या ये हमेशा से ऐसे थे? मौजूदा स्थिति क्या है? जनवरी में जब क्यूबा की स्थिति पर चर्चा हुई थी, तब मामला वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़ा था। उस समय भी क्यूबा की हालत बहुत खराब थी। रोज़ लंबे ब्लैकआउट, चरमराती अर्थव्यवस्था और कई बार पूरे देश का बिजली ग्रिड गिर जाना। सरकार हर बार किसी तरह अस्थायी मरम्मत करके स्थिति संभाल रही थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब वेनेजुएला से आने वाला तेल बंद हो गया। यहीं से क्यूबा की ऊर्जा संकट की असली शुरुआत हुई। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल मैक्सिको क्यूबा का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया था। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम ने कहा था कि वे पहले से हुए तेल समझौतों को निभाएँगी। उन्होंने इसे मानवीय और संप्रभुता का मामला बताया था। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम ने कहा था कि वे पहले से हुए तेल समझौतों को निभाएँगी। उन्होंने इसे मानवीय और संप्रभुता का मामला बताया था। लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका की रणनीति साफ दिख रही है। क्यूबा के पास आने वाला हर डॉलर, हर बैरल तेल और हर रास्ता बंद कर देना।

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के एकलौते राष्ट्रपति नहीं हैं जो क्यूबा पर सख्त हो रहे हैं। क्यूबा और अमेरिका के बीच की दुश्मनी कई दशकों पुरानी है। 1898 में अमेरिका ने स्पेन को हराया। जिसके बाद स्पेन ने क्यूबा पर अपने सभी दावों को छोड़ दिया। इसे अमेरिका को सौंप दिया। साल 1902 में क्यूबा स्वतंत्र हुआ और टॉमस इस्ट्राडा पाल्मा इसके पहले राष्ट्रपति बने। लेकिव प्लैट संशोधन के कारण द्वीप अमेरिकी संरक्षण में रहा और इसके कारण अमेरिका को क्यूबाई मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिला। कुछ साल बाद क्यूबा की राजनीति फिर उथल-पुथल में फँस गई। राष्ट्रपति इस्ट्राडा को इस्तीफा देना पड़ा और होजे मिगुएल गोमेज़ के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद अमेरिका ने क्यूबा में हस्तक्षेप कर दिया। इसके बाद 1909 में अमेरिका की निगरानी में चुनाव कराए गए, जिनमें होजे मिगुएल गोमेज़ राष्ट्रपति बने। लेकिन उनका कार्यकाल भी विवादों से घिर गया और उन पर जल्द ही भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। 1912 में जब क्यूबा में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ़ अश्वेत समुदाय ने विरोध प्रदर्शन शुरू किए, तो हालात संभालने के लिए अमेरिकी सेना एक बार फिर क्यूबा में उतरी और आंदोलन को दबाने में मदद की। इसके कुछ साल बाद, 1933 में क्यूबा की राजनीति में एक और बड़ा मोड़ आया। सेना के अफसर फुलगेन्सियो बतिस्ता के नेतृत्व में तख्तापलट हुआ और तत्कालीन राष्ट्रपति जेरार्डो मचाडो को सत्ता से हटा दिया गया। बतिस्ता का शासन लंबे समय तक चला, लेकिन इसके खिलाफ असंतोष बढ़ता गया। 1953 में फ़िदेल कास्त्रो ने बतिस्ता सरकार के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की, हालांकि यह पहली कोशिश सफल नहीं हो पाई। विदेश नीति के विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका और क्यूबा के बीच असली टकराव की शुरुआत 1959 में हुई। उसी साल फ़िदेल कास्त्रो की क्रांति सफल हुई और उन्होंने अमेरिका समर्थित सरकार को सत्ता से हटा दिया। शुरुआत में अमेरिका ने कास्त्रो की नई सरकार को स्वीकार कर लिया था। लेकिन हालात तब बदलने लगे जब क्यूबा ने अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी सोवियत संघ से रिश्ते मजबूत करने शुरू किए और उसके साथ व्यापार बढ़ाया। इसके साथ ही क्यूबा सरकार ने अमेरिकी कंपनियों की संपत्तियों को अपने नियंत्रण में ले लिया और अमेरिकी उत्पादों पर भारी टैक्स लगा दिया। यहीं से दोनों देशों के रिश्तों में गहरी दरार पड़ गई और अमेरिका-क्यूबा दुश्मनी की नींव मजबूत हो गई।

1961 में अमेरिका ने क्यूबा में फ़िदेल कास्त्रो की सरकार गिराने के लिए एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया। इस ऑपरेशन को इतिहास में "बे ऑफ़ पिग्स इनवेज़न" के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने कास्त्रो सरकार के विरोध में मौजूद क्यूबाई विद्रोहियों और निर्वासित लोगों को सैन्य प्रशिक्षण, हथियार और आर्थिक मदद दी। योजना यह थी कि ये विद्रोही क्यूबा में हमला करेंगे और जनता का समर्थन मिलते ही कास्त्रो की सरकार गिर जाएगी। लेकिन यह योजना पूरी तरह फेल हो गई। इस असफलता की एक बड़ी वजह यह भी थी कि अमेरिका की ओर से वादा की गई हवाई सहायता समय पर नहीं पहुंच सकी।

अभियान

नंदी के मुख से बहती अनवरत जलधारा: बेंगलुरु के रहस्यमयी शिवधाम की अद्भुत कथा

भारत को प्राचीन काल से ही मंदिरों, आस्था और आध्यात्मिक रहस्यों की भूमि माना जाता है। यहां के अनेक मंदिर केवल पूजा-अर्चना के स्थान ही नहीं हैं, बल्कि उनके साथ जुड़ी कहानियां, चमत्कार और परंपराएं लोगों को आश्चर्य से भर देती हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे कई मंदिर हैं जहां कोई न कोई अद्भुत घटना या परंपरा सदियों से चली आ रही है। इन्हीं रहस्यमयी स्थलों में से एक दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी Bengaluru में स्थित प्रसिद्ध Kadu Malleshwara Temple है। इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यहां नंदी की पत्थर की प्रतिमा के मुख से लगातार जलधारा निकलती रहती है और यह जल सीधे शिवलिंग पर गिरकर स्वयं भगवान शिव का अभिषेक करती है। आश्चर्य की बात यह है कि यह जलधारा सदियों से निरंतर बह रही है और इसका स्पष्ट स्रोत आज तक ज्ञात नहीं हो पाया है।

इस अद्भुत घटना ने न केवल भक्तों को बल्कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी चकित किया है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु इसे भगवान शिव की दिव्य लीला और चमत्कार मानते हैं, जबकि कई विद्वान इसके पीछे छिपे प्राकृतिक कारणों को समझने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन अब तक इस रहस्य का कोई निश्चित वैज्ञानिक उत्तर सामने नहीं आया है। यही कारण है कि यह मंदिर आस्था और रहस्य का अनोखा संगम बन गया है।

इतिहासकारों के अनुसार काडू मल्लेश्वर मंदिर का निर्माण लगभग चार सौ वर्ष पहले हुआ था। माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में मराठा शासक परिवार से जुड़े वेंकोजी भोसले ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वेंकोजी महान मराठा शासक Shivaji के भाई माने जाते हैं और दक्षिण भारत में मराठा शासन के विस्तार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उस समय यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था, इसलिए इस मंदिर का नाम "काडू मल्लेश्वर" पड़ा। कन्नड़ भाषा में "काडू" का अर्थ जंगल होता है और "मल्लेश्वर" भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। इसमें मराठा और द्रविड़ शैली का सुंदर संगम दिखाई देता है। मंदिर के पत्थरों पर की गई नक्काशी, विशाल प्रांगण और प्राचीन संरचना इस बात का प्रमाण हैं कि इसे अत्यंत कुशल शिल्पकारों ने बनाया था। यहां स्थापित शिवलिंग को कई भक्त Mallikarjuna Jyotirlinga का स्वरूप भी मानते हैं और इसे अत्यंत पवित्र मानकर पूजा करते हैं।

इस मंदिर के पास स्थित एक और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है Dakshinamukha Nandi Teertha Kalyani। यह स्थान काडू मल्लेश्वर मंदिर की आध्यात्मिक परंपरा का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार जब तक श्रद्धालु नंदी तीर्थ के दर्शन नहीं करते, तब तक काडू मल्लेश्वर मंदिर की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए मंदिर आने वाले अधिकांश भक्त पहले नंदी तीर्थ जाते हैं और फिर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। नंदी तीर्थ में स्थित नंदी महाराज की विशाल पत्थर की प्रतिमा इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता है। इस प्रतिमा के मुख से लगातार स्वच्छ और ठंडा पानी निकलता रहता है। यह जल एक छोटी धारा के रूप में बहते हुए सीधे शिवलिंग पर गिरता है और इस प्रकार भगवान शिव का प्राकृतिक जलाभिषेक होता रहता है। यह दृश्य देखने वालों के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक होता है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं नंदी भगवान शिव की पूजा कर रहे हों।

सबसे बड़ी बात यह है कि यह जलधारा वर्ष भर निरंतर बहती रहती है। मौसम बदलने, वर्षा या सूखे के बावजूद इसका प्रवाह कभी पूरी तरह बंद नहीं होता। यही कारण है कि लोग इसे चमत्कारी घटना मानते हैं। कई वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों ने इस जलधारा के स्रोत को खोजने की कोशिश की है। कुछ लोगों का अनुमान है कि यह किसी प्राचीन भूमिगत जलस्रोत से जुड़ी हो सकती है, लेकिन अब तक इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पाया है। इसलिए यह रहस्य आज भी लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाता रहता है।

भक्तों के लिए यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि गहरी आस्था का केंद्र है। यहां आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान शिव की कृपा से यहां हर मनोकामना पूरी होती है। लोग अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाने, सुख-समृद्धि और मानसिक शांति के लिए यहां प्रार्थना करते हैं। कई भक्त बताते हैं कि यहां की शांति और आध्यात्मिक वातावरण उन्हें भीतर से सुकून देता है।

हर वर्ष Maha Shivaratri के अवसर पर इस मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। इस दौरान मंदिर परिसर को फूलों और रंग-बिरंगी रोशनियों से सजाया जाता है। भगवान शिव का विशेष रुद्राभिषेक और महापूजा की जाती है। हजारों श्रद्धालु पूरी रात जागकर भजन-कीर्तन करते हैं और भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं। इस अवसर पर मंदिर परिसर में एक भव्य रथयात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें भगवान शिव की प्रतिमा को सजाए गए रथ पर पूरे क्षेत्र में घुमाया जाता है। महाशिवरात्रि के समय यहां लगने वाला प्रसिद्ध मूंगफली मेला भी लोगों को आकर्षित करता है। यह मेला लगभग पंद्रह दिनों तक चलता है और इसमें आसपास के गांवों और शहरों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस मेले में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिलती है। कई परिवार हर वर्ष इस मेले में शामिल होने की परंपरा निभाते हैं। बेंगलुरु शहर में स्थित होने के कारण इस मंदिर तक पहुंचना भी बहुत आसान है। हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए Kempegowda International Airport सबसे निकट का हवाई अड्डा है। वहीं रेल मार्ग से आने वाले यात्रियों के लिए Bengaluru City Railway Station सुविधाजनक विकल्प है। शहर के विभिन्न हिस्सों से मेट्रो, बस और टैक्सी की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध है, जिससे मंदिर तक पहुंचना सरल हो जाता है।

मंदिर के आसपास रहने की व्यवस्था भी अच्छी है। मल्लेश्वरम और आसपास के क्षेत्रों में कई धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस और मध्यम श्रेणी के होटल उपलब्ध हैं, जहां श्रद्धालु आराम से ठहर सकते हैं। यहां आने वाले पर्यटक न केवल मंदिर के दर्शन करते हैं बल्कि बेंगलुरु शहर की अन्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगहों को भी देखने का अवसर प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार काडू मल्लेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का अद्भुत संगम है। नंदी के मुख से बहती जलधारा आज भी लोगों के लिए एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है, लेकिन भक्तों के लिए यह भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है। सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी हजारों लोगों को आकर्षित करती है और उन्हें यह अनुभव कराती है कि भारत की आध्यात्मिक विरासत कितनी गहरी और अद्भुत है। यहां आने वाला हर व्यक्ति इस स्थान की शांति, आस्था और रहस्यमयी वातावरण को महसूस करता है और अपने साथ एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव लेकर लौटता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं में खुली टकराहट, मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर के बीच पत्रों से बढ़ा सियासी विवाद

(जीएनएस)। New Delhi। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी Indian National Congress के भीतर एक नया वैचारिक विवाद सामने आया है। पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं Mani Shankar Aiyar और Shashi Tharoor के बीच सार्वजनिक रूप से मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को खुले पत्र लिखकर अपने विचार रखे और एक-दूसरे के रुख पर तीखी टिप्पणियां कीं। इस घटनाक्रम ने कांग्रेस के भीतर चल रही वैचारिक बहस को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब मणिशंकर अय्यर ने शशि थरूर के नाम एक खुला पत्र लिखा, जो इस सप्ताह की शुरुआत में एक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इस पत्र में अय्यर ने थरूर के हालिया बयान और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उनके रुख को लेकर गहरी निराशा व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि एक टेलीविजन कार्यक्रम में थरूर द्वारा पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और वैश्विक राजनीति को लेकर दिए गए जवाब ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। अय्यर का मानना था कि इस संघर्ष में Israel अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ मिलकर युद्ध कर रहा है और इसे उन्होंने "गैरकानूनी और पापपूर्ण युद्ध" बताया।

अय्यर ने अपने पत्र में यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि शशि थरूर का राजनीतिक और वैचारिक रुख अब कांग्रेस की पारंपरिक सोच से अलग होता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि थरूर के बयानों और गतिविधियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मन में वर्तमान केंद्र सरकार और उसकी नीतियों के प्रति सहानुभूति बढ़ गई है। अय्यर ने विशेष रूप से भारत के विदेश मंत्री Subrahmanyam Jaishankar की नीतियों की प्रशंसा करने को लेकर भी थरूर पर निशाना साधा और इसे "नैतिक समर्पण" जैसा बताया।

मणिशंकर अय्यर ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान उन्होंने कभी थरूर का समर्थन किया था, लेकिन अब उन्हें उस निर्णय पर पछतावा हो रहा है। उनके अनुसार दोनों नेताओं की राजनीतिक सोच और दृष्टिकोण अब इतने अलग हो चुके हैं कि वे स्वयं को थरूर से अलग रास्ते पर खड़ा पाते हैं। अय्यर ने यह भी याद दिलाया कि सबरीमाला मंदिर से जुड़े विवाद में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे पर थरूर का रुख भी उन्हें उस समय असहज लगा था।

इस खुले पत्र के सामने आने के बाद शशि थरूर ने भी सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अय्यर के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके विचारों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। थरूर ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर व्यावहारिक दृष्टिकोण रखना जरूरी होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैश्विक राजनीति की जटिलताओं और भारत के आर्थिक तथा रणनीतिक हितों को समझना जिम्मेदार नेतृत्व की पहचान है।

थरूर ने यह भी कहा कि उनके बारे में यह कहना कि वे किसी सरकार को खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं, पूरी तरह गलत है। उन्होंने अपनी विदेश यात्राओं और सार्वजनिक गतिविधियों को निजी और वैचारिक बताया तथा कहा कि इनका उद्देश्य केवल वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका और चुनौतियों को समझना है। उनके अनुसार लोकतंत्र में विचारों की विविधता और असहमति का सम्मान होना चाहिए।

अपने जवाब में थरूर ने यह भी कहा कि वे मणिशंकर अय्यर का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते हैं और अतीत में मिले उनके समर्थन के लिए आभारी हैं। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि व्यक्तिगत टिप्पणियां और उनके इरादों पर सवाल उठाना उचित नहीं है। थरूर ने कहा कि राजनीतिक बहसें तथ्यों और विचारों के आधार पर होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत आरोपों के आधार पर।

इस पूरे विवाद ने कांग्रेस के भीतर वैचारिक दिशा और रणनीति को लेकर चल रही बहस को फिर से उजागर कर दिया है। पार्टी के भीतर लंबे समय से यह चर्चा चलती रही है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों, आर्थिक नीतियों और सामाजिक प्रश्नों पर पार्टी का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। कुछ नेता परंपरागत विचारधारा पर जोर देते हैं, जबकि कुछ अन्य अधिक व्यावहारिक और समकालीन दृष्टिकोण अपनाने की बात करते हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर के बीच यह विवाद केवल व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस के भीतर विचारधारात्मक बहस का एक उदाहरण भी है। दोनों नेता लंबे समय से विदेश नीति और वैश्विक राजनीति पर सक्रिय रूप से बोलते रहे हैं, लेकिन कई मुद्दों पर उनके दृष्टिकोण अलग रहे हैं।

फिलहाल यह विवाद कांग्रेस के भीतर चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि पार्टी नेतृत्व की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह बहस जारी है कि आने वाले समय में यह मतभेद किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और क्या यह पार्टी की आंतरिक राजनीति पर भी असर डाल सकता है।

गैर-किराया राजस्व (NFR) में भावनगर रेलवे मंडल का दबदबा,वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सहित 06 रेल अधिकारी-कर्मचारी सम्मानित

(जीएनएस)।पश्चिम रेलवे ने गैर-किराया राजस्व (Non-Fare Revenue – NFR) के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए लगातार दूसरे वर्ष संपूर्ण भारतीय रेल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस गौरवपूर्ण सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पश्चिम रेलवे के विभिन्न मंडलों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिनांक 11.03.2026 (बुधवार) को चर्चगेट स्थित मुख्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रिंसिपल मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (PCCM) श्री तरुण जैन द्वारा सम्मानित किया गया।

इस उपलब्धि के क्रम में भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (Sr. DCM) श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व तथा वाणिज्य विभाग की टीम के उत्कृष्ट कार्य की सराहना की गई। इस अवसर पर भावनगर मंडल के दो (02) अधिकारियों एवं चार (04) कर्मचारियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (यात्री सेवाएं) श्री स्वप्निल वालिंगकर सहित मुख्यालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

भावनगर मंडल की उपलब्धियां

उल्लेखनीय है कि पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा गैर-किराया राजस्व (Non-Fare Revenue) के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मंडल ने लगभग 3.89 करोड़ का गैर-किराया राजस्व अर्जित किया। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 (फरवरी 2026 तक) के दौरान मंडल द्वारा लगभग 3.94 करोड़ का गैर-किराया राजस्व प्राप्त किया गया है।

मंडल द्वारा राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न नवाचारी पहलों को लागू किया गया है। इसी क्रम में पहली बार भावनगर मंडल में जूनागढ़ स्टेशन पर गेम ज़ोन, डीआरएम कार्यालय कैंटीन, मंडल रेलवे अस्पताल कैंटीन, वेरावल स्टेशन पर रिटायरिंग रूम/वेटिंग हॉल/वेटिंग रूम तथा वेरावल स्टेशन पर क्लोक रूम के लिए अनुबंध प्रदान किए गए हैं। इन पहलों के माध्यम से मंडल को गैर-किराया राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त हुई है।

सम्मानित होने वाले भावनगर मंडल के अधिकारी-कर्मचारी

वाणिज्य विभाग में उत्कृष्ट कार्य के लिए भावनगर मंडल के जिन अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, उनके नाम इस प्रकार हैं –

1.श्री अतुल कुमार त्रिपाठी – वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भावनगर

2.सुश्री निलादेवी झाला – मंडल वाणिज्य प्रबंधक, भावनगर

3.श्री जिंजाला जगदिश मनसुखभाई – मंडल वाणिज्य निरीक्षक (गैर-किराया राजस्व)

4.श्री जादव दर्शन घनश्यामभाई – जूनियर क्लर्क

5.श्री शशिकांत शर्मा – सीसी/टीसी

6.श्री भार्गव पंडया – मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, भावनगर

भावनगर मंडल की इस उपलब्धि ने न केवल मंडल की प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ किया है, बल्कि पश्चिम रेलवे को भारतीय रेल में अग्रणी बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस अवसर पर भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने वाणिज्य विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया।

ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा—केवल आय नहीं, माता-पिता का पद और सामाजिक स्थिति भी होगी आधार

(जीएनएस)। New Delhi। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के क्रीमी लेयर से जुड़े एक अहम मामले में Supreme Court of India ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी अभ्यर्थी को क्रीमी लेयर में शामिल करने का निर्णय केवल माता-पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय अभिभावकों के पद, सेवा श्रेणी और सामाजिक स्थिति जैसे पहलुओं को भी समान रूप से ध्यान में रखना जरूरी है। यह फैसला ओबीसी आरक्षण से जुड़े कई मामलों के लिए मार्गदर्शक माना जा रहा है। न्यायमूर्ति P. S. Narasimha और न्यायमूर्ति R. Mahadevan की खंडपीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि केवल आय को आधार बनाकर किसी अभ्यर्थी को आरक्षण से बाहर करना उचित नहीं है। अदालत ने टिप्पणी की कि क्रीमी लेयर की अवधारणा सामाजिक और प्रशासनिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी, इसलिए इसके निर्धारण में कई कारकों का समग्र मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन कई अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बावजूद नियुक्ति प्राप्त नहीं की थी। केंद्र सरकार ने उनके माता-पिता की सैलरी को आधार बनाकर उन्हें क्रीमी लेयर में शामिल कर दिया था और इस आधार पर उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि इस प्रकार का निर्णय क्रीमी लेयर के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।

पीठ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अधिकारियों ने उम्मीदवारों को आरक्षण से बाहर करने के लिए गलत मानदंड अपनाया। अदालत के अनुसार क्रीमी लेयर का उद्देश्य उन परिवारों को आरक्षण से बाहर करना है जो सामाजिक और प्रशासनिक रूप से पहले ही सशक्त हो चुके हैं, न कि केवल इसलिए कि उनकी आय एक निश्चित सीमा से अधिक है। इसलिए किसी अभ्यर्थी की स्थिति तय करते समय उसके माता-पिता के पद, सेवा श्रेणी और सामाजिक प्रभाव को भी देखा जाना चाहिए।

यह मामला मुख्य रूप से उन उम्मीदवारों से जुड़ा था जिनके माता-पिता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों या इसी तरह के संस्थानों में कार्यरत थे। सरकार ने वर्ष 2004 में जारी एक स्पष्टीकरण पत्र का हवाला देते हुए उनकी सैलरी को आय में जोड़ लिया था। इसी आधार पर कई

पश्चिम रेलवे और एक्सिस बैंक के बीच समझौता ज्ञापन (MoU)

दो दिवंगत रेल कर्मचारियों के परिजनों को 10-10 लाख की वित्तीय सहायता

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल और एक्सिस बैंक के मध्य हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के अंतर्गत आज दिनांक 12.03.2026 को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर एक्सिस बैंक की ओर से दो दिवंगत रेल कर्मचारियों के आश्रित परिजनों को 10-10 लाख की वित्तीय सहायता राशि के चेक प्रदान किए गए।

वित्तीय सहायताः दिवंगत कर्मचारी श्री मोहनलाल मीना (TCM-I, टेलिकॉम/महेसाणा) तथा श्री महेशकुमार लिम्बाचिया (लोको पायलट, CTCC/अहमदाबाद) की प्राकृतिक मृत्यु के उपरांत उनके परिजनों को 10-10 लाख की सहायता राशि का चेक मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश, एक्सिस बैंक के डायरेक्टर श्री गुरविंदरजीत सिंह संधु एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में सौंपी गई।

बीमा सुरक्षाः वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री सिद्धार्थ ने बताया कि इस MoU के तहत रेल कर्मचारियों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ व्यापक बीमा लाभ भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। MoU के तहत मिलने वाले मुख्य लाभः एक्सिस बैंक और अहमदाबाद मंडल के बीच हुए इस समझौते के तहत कर्मचारियों के 'जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट' खोले जाते हैं, जिनमें निम्नलिखित सुरक्षा कवर शामिल हैं:

1.व्यक्तिगत दुर्घटना बीमाः दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता पर 100 लाख तक का कवर।

2.प्राकृतिक मृत्यु कवरः 60 वर्ष की आयु तक प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में 10 लाख का ग्रुप टर्म लाइफ कवर।

3.शिक्षा सहायताः दुर्घटना मृत्यु के मामलों में बच्चों की शिक्षा हेतु 8 लाख तक की सहायता।

4.विकलांगता लाभः आंशिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में मूल कवर का 75% तक लाभ।

मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने इस अवसर पर कहा, "पश्चिम रेलवे और एक्सिस बैंक के बीच हुआ यह समझौता हमारे रेल कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। इससे न केवल कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सेवाएं मिल रही हैं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में उनके परिजनों को सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा भी सुनिश्चित हो रही है।"

सूरत नगर निगम में भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद भी, सफाईकर्मियों सहित रिक्त पदों को भरने की मांग बनी रही

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत नगर निगम आयुक्त नागराजन को अधिकारी श्रेणी और तकनीकी क्लर्क आदि पदों को भरने के लिए आज जारी किए गए विज्ञापन के लिए हार्दिक बधाई। सूरत नगर निगम में पिछले 9 वर्षों से अधिक समय से सफाईकर्मी, बेलदार, क्लर्क, तकनीकी सहायक, ड्राइवर, स्टाफ नर्स, जूनियर फार्मासिस्ट, रखरखाव सहायक, मार्शल (चौकीदारी), नगर योजनाकार, चिकित्सा अधिकारी, सहायक अभियंता, प्रयोगशाला तकनीशियन, चिड़ियाघर कर्मचारी आदि के पद रिक्त थे, लेकिन लंबे समय से भर्ती नहीं हुई थी। गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस, जो अब कर्मचारियों के हितों से अवगत है और सूरत नगर निगम को इन रिक्तियों को भरने के लिए जागरूक कर रही है, ने सूरत नगर निगम आयुक्त, महापौर और स्थायी समिति के अध्यक्ष को बार-बार लिखित और मौखिक अभ्यावेदन दिए हैं। हालांकि, निर्दयी शासकों द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण, अंततः इस संगठन ने चरणबद्ध तरीके से अभ्यावेदन दिए।

शून्य त्रुटि विज्ञापन

04/07/2024, 03/01/2025, 27/11/2025 और 24/12/2025 को लिखित और मौखिक अभ्यावेदन दिए जाने के बावजूद, ऐसा प्रतीत होता है कि सूरत नगर निगम के महापौर, कार्यवाहक महापौर और स्थायी समिति के अध्यक्ष जैसे कर्मचारियों/अधिकारियों की भर्ती रोक दी गई है। जैसे ही इनका कार्यकाल समाप्त होता है, भर्ती विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाता है। सूरत नगर निगम ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के क्लर्क, तकनीकी सहायक, चालक, स्टाफ नर्स, जूनियर फार्मासिस्ट, रखरखाव सहायक, मार्शल (चौकीदारी), नगर योजनाकार, चिकित्सा अधिकारी, सहायक अभियंता, प्रयोगशाला तकनीशियन, चिड़ियाघर कर्मचारी आदि पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है, लेकिन

सफाई कर्मचारी, बेलदारो, आया, वार्डबॉय आदि पदों पर भर्ती करने से

कौन रोक रहा है? इन पदों पर भर्ती के लिए तत्काल विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। सूरत नगर निगम का क्षेत्रफल काफी बढ़ गया है, लेकिन स्वच्छता का महत्वपूर्ण कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों और बेलदारों के 6000 से अधिक पद रिक्त हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के 4000 से अधिक पद भी रिक्त हैं। शहर का क्षेत्रफल बढ़ने के साथ-साथ कर्मचारियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। वर्ष 2022 में आम सभा में सफाई कर्मचारियों, बेलदारों और अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों के लगभग 1500 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव पारित किया गया था। लेकिन आज तक उस प्रस्ताव का ठीक से पालन नहीं हुआ है। निर्वाचित पार्षदों को केवल अपने काम में ही रुचि थी।

ठेकेदार, सूरत नगर निगम द्वारा संविदा पर रखे गए सफाई कर्मचारियों, ड्राइवरों, कंप्यूटर ऑपरेटरों और नर्सिंग स्टाफ के लिए निर्धारित वेतन का आधा भी नहीं देते हैं। नगर निगम के अधिकारी और पदाधिकारी ऐसा करने के लिए विवश हैं क्योंकि वे ठेकेदारों से कुछ नहीं मांग सकते। कर्मचारियों के कम वेतन का मुद्दा उठाने पर अधिकारियों ने इस मामले को टाल दिया, मानो वे पदाधिकारियों और ठेकेदारों से डरते हों। सूरत नगर निगम के कार्यकारी कार्मिक अधिकारी के पत्र संख्या GAD/EST/P/U/80, दिनांक 03/08/2024 के अनुसार, सूरत नगर निगम द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर, नर्स, वार्ड बॉय, आया और सफाई कर्मचारियों को भुगतान किया जाने वाला वेतन क्रमशः 19300/-, 19080/-, 22601/-, 19505/-, 19505/-, 19505/-, 19505/-, 19505/- है।

लेकिन ठेकेदार द्वारा दिया जाने वाला वेतन क्रमशः 9000/-, 9000/-, 15000/-, 9000/-, 9000/-, 9000/- है। इस शोषणकारी पद्धति के खिलाफ यूनियनों के बार-बार विरोध के बावजूद, कर्मचारियों का वित्तीय शोषण जारी है और ठेकेदारों को कर्मचारियों से अधिक वेतन मिलता है। इन सभी तथ्यों से अवगत होने के बावजूद, अधिकारियों और पदाधिकारियों ने ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। गुजरात प्रदेश नगर निगम कर्मचारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाई लाल बी. वैष्णव, महासचिव कांतिभाई सोलंकी, अखिल भारतीय सफाई मजदूर के अध्यक्ष शशिकांतभाई सोलंकी, सूरत नगर निगम कर्मचारी (स्टाफ) के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल शेख और महासचिव देवेंद्र प्रजापति आदि ने सूरत नगर निगम के सभी रिक्त पदों को भरने की मांग की है।

ऊर्जा संकट पर लोकसभा में तीखी बहस, राहुल गांधी का तंज - 'संसद से नरेंद्र गायब, देश से सिलेंडर गायब'

(जीएनएस)। New Delhi। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे उसके असर को लेकर गुरुवार को Lok Sabha में जोरदार बहस देखने को मिली। विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए ऊर्जा संकट, एलपीजी की कमी और बढ़ती कीमतों को लेकर कई सवाल उठाए। इस दौरान Rahul Gandhi ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में स्थिति यह हो गई है कि "संसद से नरेंद्र गायब हैं और देश से सिलेंडर गायब हो रहे हैं।" उनके इस बयान के बाद सदन में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

राहुल गांधी ने अपने भाषण में पश्चिम एशिया में जारी Iran–Israel conflict का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका असर केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका वैश्विक ऊर्जा बाजार और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि यदि स्थिति और बिगड़ती है और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं, तो भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देश के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है।

अपने संबोधन में राहुल गांधी ने विशेष रूप से Strait of Hormuz का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है और वैश्विक स्तर पर लगभग 20 प्रतिशत कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। भारत की ऊर्जा आपूर्ति का भी एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग पर निर्भर है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह मार्ग किसी कारण से बंद हो जाता है या वहां तनाव बढ़ता है, तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है।

राहुल गांधी ने कहा कि युद्ध और अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण देश में एलपीजी की आपूर्ति पर भी असर दिखाई देने लगा है। उन्होंने दावा किया कि कई जगह गैस सिलेंडर की उपलब्धता कम हो रही है और इससे आम लोगों के साथ-साथ छोटे व्यवसायियों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे होटल, रेस्तरां और खाने-पीने का कारोबार करने वाले लोग इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है वह केवल शुरुआत हो सकती है। यदि पश्चिम एशिया में तनाव लंबा खिंचता है, तो इसका असर और व्यापक हो सकता है। राहुल गांधी के अनुसार सरकार को इस संभावित संकट के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए और देश की ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए ठोस रणनीति बनानी चाहिए।

लोकसभा में अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े और स्वतंत्र देश को यह तय करने का पूरा अधिकार होना चाहिए कि वह किस देश से तेल और गैस खरीदेगा। उनके अनुसार ऊर्जा नीति के मामले में भारत को किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त होकर अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।

इस संदर्भ में उन्होंने यह भी कहा कि यदि भारत को रूस या किसी अन्य देश से ऊर्जा आयात करना उसके आर्थिक हित में है, तो उसे ऐसा करने से रोका नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी दूसरे देश को यह तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि भारत किससे व्यापार करे या किससे नहीं।

अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के एक पुराने बयान का भी जिक्र किया और कहा कि भारत की विदेश नीति और ऊर्जा रणनीति पर किसी अन्य देश का प्रभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र और स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए।

बहस के दौरान राहुल गांधी ने कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए, जिससे सदन में माहौल और गरमा गया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास एक दस्तावेज है, जिसमें कथित रूप से यह उल्लेख है कि पेट्रोलियम मंत्री Hardeep Singh Puri की बेटी को अंतरराष्ट्रीय निवेशक George Soros से धन प्राप्त हुआ था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मंत्री ने स्वयं को कभी Jeffrey Epstein का मित्र बताया था।

राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद सत्ता पक्ष की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। ट्रेजरी बेंच से कई सांसदों ने उनके बयान का विरोध किया और सदन में शोर-शराबा शुरू हो गया। माहौल इतना गर्म हो गया कि कुछ समय के लिए कार्यवाही बाधित होने की स्थिति बन गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष Om Birla को हस्तक्षेप करना पड़ा।

पश्चिम रेलवे का गैर-किराया राजस्व दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य

(जीएनएस)। प्रधानमंत्री कार्यालय के भारतीय रेल के गैर-किराया राजस्व (NFR) को बढ़ाने के निर्देशों के अनुरूप, पश्चिम रेलवे ने गैर-किराया स्रोतों से अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री तरुण जैन ने गैर-किराया राजस्व बढ़ाने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श के लिए पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधकों के साथ एक उच्चस्तरीय विचार-मंथन बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान श्री तरुण जैन ने कहा कि "हमारा उद्देश्य यात्रियों को मूल्यवर्धित सेवाएँ प्रदान करना है। हमारे डिजिटल लाउंज और मिनी मॉल की सफलता यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यात्री अब आधुनिक, प्रौद्योगिकी आधारित तथा गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। गैर-किराया राजस्व को दोगुना कर हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पश्चिम रेलवे अपने वाणिज्यिक परिसंपत्तियों की राजस्व क्षमता को नए दृष्टिकोण से देखे।"

चालू वित्तीय वर्ष में फरवरी 2026 तक पश्चिम रेलवे ने गैर-किराया राजस्व के रूप में 117 करोड़ अर्जित किए हैं, जिससे पश्चिम रेलवे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जोनों में शामिल हो गया है। भारतीय रेल के गैर-किराया राजस्व को 750 करोड़ से बढ़ाकर 1,500 करोड़ करने के राष्ट्रीय निर्देश के अनुरूप, पश्चिम रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 239.24 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री तरुण जैन ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुंबई सेंट्रल स्थित डिजिटल लाउंज, रतलाम स्टेशन पर मिनी मॉल तथा अहमदाबाद में एसी सह डिजिटल लाउंज जैसे सफल नवाचार पहलों को दोहराने की आवश्यकता होगी, जिन्हें सराहना मिल चुकी है। ये पहल यात्रियों की सुविधा और आराम को अधिकतम करने के उद्देश्य से की गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि समय की मांग है कि पारंपरिक विज्ञापन के दायरे से आगे बढ़कर नवोन्मेषी दृष्टिकोण अपनाए जाएँ। बैठक के दौरान कुछ नई पहल पर चर्चा की गई, जिनमें पश्चिम रेलवे पर उपयुक्त स्थानों की पहचान कर ब्रांडेड कियोस्क और एक्सपीरियंस जोन, परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण, अधिक यात्री आवागमन वाले स्टेशनों पर डिजिटल आउट-ऑफ-होम (DOOH) विज्ञापन का विस्तार तथा रेलवे स्टेशनों को सजीव वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में विकसित करना शामिल है।

राज्य की आईटीआई में मोटर मैकेनिक ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से जुड़ा प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को 40 इलेक्ट्रिक कारों का वितरण किया

▸▸ श्रम एवं कौशल विकास मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावळिया की प्रेरक उपस्थिति

▸▸ मुख्यमंत्री ने गांधीनगर में निर्माण और संगठित क्षेत्र के श्रमयोगियों को घर के आसपास ही प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध कराने के लिए 50 धन्वंतरि आरोग्य रथ और 6 मोबाइल मेडिकल वैन का लोकार्पण किया

(जीएनएस)। गांधीनगर : राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में मोटर मैकेनिक ट्रेड के 8000 से अधिक युवा प्रशिक्षु अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी नई टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस उद्देश्य से श्रम एवं कौशल विकास मंत्री श्री कुंवरजीभाई बावळिया की उपस्थिति में गुरुवार को गांधीनगर में विभिन्न जिलों की आईटीआई के लिए 40 इलेक्ट्रिक कारों का वितरण किया।

इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते दायरे और इस क्षेत्र में खुलने वाले रोजगार के अपार अवसरों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को इसके अनुरूप आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित करने की प्रक्रिया शुरू की है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में बैटरी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक पावरट्रेन और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के विशेषज्ञों की मांग भी लगातार बढ़ रही है।

इस संदर्भ में, राज्य सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के व्यवसायों के लिए आईटीआई को सिलेबस आधारित

40 इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध कराकर प्रशिक्षुओं को नवीनतम टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, ताकि उद्योगों को कुशल मानवबल उपलब्ध हो सके।

सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षु इलेक्ट्रिक वाहन और उससे जुड़े पेशे के प्रायोगिक प्रशिक्षण में सक्षम बनकर आत्मनिर्भरता हासिल कर सकें, इसके लिए नवीनतम टेक्नोलॉजी के अनुरूप प्रैक्टिकल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में ये 40 इलेक्ट्रिक कारें उपयोगी साबित होंगी।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इन 40 ईवी कारों के अलावा 50 धन्वंतरि आरोग्य रथों और 6 मोबाइल मेडिकल वैन का भी लोकार्पण किया।

निर्माण श्रमिकों और संस्थाओं के श्रमयोगियों और उनके परिवारजनों को उनके घर के आसपास ही प्राथमिक चिकित्सा उपचार मिल सके, गंभीर रोगों से बचाव हो सके और उनका स्वास्थ्य बना रहे, इस उद्देश्य से इन धन्वंतरि आरोग्य रथों में बुखार, दस्त, उल्टी और चर्म रोग जैसे साधारण रोगों सहित प्राथमिक चोटों का उपचार तथा पेशाब, खून, शुगर और मलेरिया आदि का लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है।

इतना ही नहीं, बच्चों बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान प्राथमिक उपचार देने के साथ-साथ विभिन्न निदान स्थल पर ही करके आवश्यकतानुसार दवाइयां निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

गुजरात भवन और अन्य निर्माण श्रमयोगी कल्याण बोर्ड द्वारा राज्य के सभी जिलों में 154 धन्वंतरि आरोग्य रथ और गुजरात श्रमयोगी कल्याण बोर्ड द्वारा 25 मोबाइल मेडिकल वैन सेवारत हैं।

अब, नए लोकार्पित हुए 50 धन्वंतरि आरोग्य रथों और 6 मोबाइल मेडिकल वैन के साथ राज्य के 34 जिलों में कुल 206 धन्वंतरि आरोग्य रथ और 31 मोबाइल मेडिकल वैन श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कार्यरत किए गए हैं।

इस लोकार्पण अवसर पर श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग के सचिव श्री लोचन सेहरा, रोजगार और प्रशिक्षण निदेशक श्री नितिन सांगवान, श्रम आयुक्त श्री कमलेश डी. लाखाणी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

सफाले रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 19016 पोरबंदर दादर सौराष्ट्र एक्सप्रेस के समय में आंशिक परिवर्तन

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा तथा रेलगाड़ियों की समयपालन (पंक्चुअलिटी) बनाए रखने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गाड़ी संख्या 19016 पोरबंदर–दादर सौराष्ट्र एक्सप्रेस के सफाले रेलवे स्टेशन पर आगमन एवं प्रस्थान समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है।

▸▸ वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार यह संशोधित समय दिनांक 15 मार्च 2026 से चलने वाली ट्रेन से प्रभावी होगा। संशोधित विवरण निम्नानुसार है—

▸▸ गाड़ी संख्या 19016 पोरबंदर–दादर सौराष्ट्र एक्सप्रेस

▸▸ सफाले स्टेशन पर पूर्व समय (आगमन/प्रस्थान): 17:13 / 17:15 बजे

▸▸ संशोधित समय (आगमन/प्रस्थान): 17:23 / 17:25 बजे

▸▸ अर्थात् उक्त ट्रेन अब सफाले रेलवे स्टेशन पर पूर्व निर्धारित समय से 10 मिनट बाद पहुंचेगी और प्रस्थान करेगी।

यह भी सूचित किया जाता है कि सफाले स्टेशन के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्टेशन के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

पश्चिम रेलवे यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय उपरोक्त संशोधित समय का ध्यान रखें।

गुजरात की 4 महानगर पालिकाओं में बनेंगे 'नमो स्वदेशी अर्बन मॉल', स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री के लिए उत्पादकों को मिलेगा स्थायी प्लेटफॉर्म

▸▸ गुजरात शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में एक-एक 'नमो स्वदेशी अर्बन मॉल' बनाया जाएगा

▸▸ स्थानीय कारीगरों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और फेरीवालों को स्वदेशी उत्पादों की बिक्री के लिए मिलेगा आधुनिक बाजार

(जीएनएस)। गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'हर घर स्वदेशी' जैसे अभियान शुरू किए हैं ताकि देश का प्रत्येक नागरिक स्वदेशी वस्तुओं को अपनाए और 2047 तक विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में अपना योगदान दे सके। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्यमियों को एक मंच प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलें शुरू की हैं। गुजरात में स्वदेशी मेलों के सफल आयोजन के बाद, अब अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट सहित 4 महानगर पालिकाओं में 'नमो स्वदेशी अर्बन मॉल' बनाए जाएंगे। नमो स्वदेशी अर्बन मॉल : स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री के लिए उत्पादकों को मिलेगा एक स्थायी प्लेटफॉर्म शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण विभाग के तहत गुजरात शहरी आजीविका मिशन स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'नमो स्वदेशी अर्बन मॉल' योजना क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य महानगर पालिकाओं में स्वदेशी उत्पादों की बिक्री के लिए स्थायी और आधुनिक बाजार व्यवस्था खड़ी करना है, ताकि नागरिकों को स्वदेशी उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिल सके।

उल्लेखनीय है कि शहरी विकास वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य की 16 महानगर पालिकाओं में प्लास्टिक फ्री 'स्वदेशी फेस्टिवल' के अंतर्गत स्वदेशी मेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें स्थानीय कारीगरों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, फेरीवालों और छोटे व्यापारियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर मिला था। अब, स्वदेशी उत्पादों को व्यापक और स्थायी बाजार उपलब्ध कराने के लिए अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट में स्थायी 'नमो स्वदेशी अर्बन मॉल' शुरू किए जाएंगे। ये मॉल स्थानीय कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूहों, फेरीवालों और छोटे उद्यमियों को अपने स्वदेशी उत्पादों की बिक्री के लिए एक सुव्यवस्थित और आधुनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करेंगे।

'वोकल फॉर लोकल' अभियान को मिलेगी गति इस मॉल के जरिए खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा, जिससे ग्राहकों को एक ही स्थान पर विभिन्न स्वदेशी उत्पाद आसानी से उपलब्ध होंगे और उत्पादकों को भी अपने उत्पादों के लिए बाजार मिलेगा। इसके अलावा, इस मॉल का उपयोग स्वदेशी मेलों, हाट और विभिन्न प्रदर्शनियों के लिए भी किया जा सकेगा, जिसके कारण 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को और गति मिलेगी।

राज्य सरकार द्वारा 2026-27 के बजट में 'नमो स्वदेशी अर्बन मॉल' और स्वदेशी मेलों के आयोजन के लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह पहल स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

क्रूड ऑयल वायदा में 350 रुपये, सोना वायदा में 200 रुपये और चांदी वायदा में 5009 रुपये की वृद्धि

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 155534.62 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 25132.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 130400.78 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का मार्च वायदा 40170 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 5100.36 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 12105.36 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा 162799 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 162991 रुपये और नीचे में 161076 रुपये पर पहुंचकर, 161789 रुपये के पिछले बंद के सामने 200 रुपये या 0.12 फीसदी की तेजी के संग 161989 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 187 रुपये या 0.14 फीसदी की तेजी के संग 132208 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 13 रुपये या 0.08 फीसदी की तेजी के संग 16611 रुपये प्रति 1 ग्राम हुआ। सोना-मिनी अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 161112 रुपये के भाव पर खूलकर, 162463 रुपये के दिन के उच्च और 161020 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 271 रुपये या 0.17 फीसदी की तेजी के संग 162050 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम सत्र के आरंभ में 162399 रुपये के भाव पर खूलकर, 162965 रुपये के दिन के उच्च और 161700 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 162563 रुपये के पिछले बंद के सामने 124 रुपये या 0.08 फीसदी की तेजी के संग 162687 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा 269212 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 274665 रुपये और नीचे में 266174 रुपये पर पहुंचकर, 268491 रुपये के पिछले बंद के सामने 5009 रुपये या 1.87 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 273500 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 4555 रुपये या 1.66 फीसदी की तेजी के संग 278780 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 4330 रुपये या 1.58 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 278809 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

▸▸ कमोडिटी वायदाओं में 25132 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 130400 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 12105 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार : बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 40170 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 1882.91 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा 1.1 रुपये या 0.09 फीसदी बढ़कर 1204.7 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मार्च वायदा 40 पैसे या 0.12 फीसदी बढ़कर 325.9 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 2.55 रुपये या 0.74 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 347.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मार्च वायदा 10 पैसे या 0.05 फीसदी चढ़कर 188.4 रुपये प्रति किलो हुआ। इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 10913.57 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 8431 रुपये के भाव पर खूलकर, 8829 रुपये के दिन के उच्च और 8314 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 350 रुपये या 4.32 फीसदी की बढ़त के साथ 8457 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मार्च वायदा 353 रुपये या 4.36 फीसदी की मजबूती के साथ 8458 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा 304 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 305.8 रुपये और नीचे में 293.4 रुपये पर पहुंचकर, 296.2 रुपये के पिछले बंद के सामने 70 पैसे या 0.24 फीसदी घटकर 295.5 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 70 पैसे या 0.24 फीसदी टूटकर 295.6 रुपये प्रति एमएमबीटीयू हुआ। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा 1004 रुपये पर खूलकर, 5.6 रुपये या 0.56 फीसदी गिरकर 992.9 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 6599.05 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 5506.32 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 1070.36 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 632.82 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 2.23 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 169.76 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 8669.09 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2213.30 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 5.36 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 1.28 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 10684 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 61393 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 30481 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 431797 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 61611 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 6802 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 18243 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 65990 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 28757 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 25643 लोट के स्तर पर था। इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 40100 पॉइंट पर खूलकर, 40200 के उच्च और 40100 के नीचले स्तर को छूकर, 137 पॉइंट बढ़कर 40170 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मार्च 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 44.6 रुपये की बढ़त के साथ 293 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.05 रुपये की गिरावट के साथ 19.25 रुपये हुआ।

सोना मार्च 165000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 175.5 रुपये की गिरावट के साथ 2173 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 350000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 34 रुपये की गिरावट के साथ 865 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 87 पैसे की नरमी के साथ 24.24 रुपये हुआ। जस्ता मार्च 330 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.18 रुपये की बढ़त के साथ 3.9 रुपये हुआ। पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मार्च 7000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 84.4 रुपये की गिरावट के साथ 109.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 55 पैसे के सुधार के साथ 24.55 रुपये हुआ।

सोना मार्च 160000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 344 रुपये की गिरावट के साथ 2437 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 437.5 रुपये की गिरावट के साथ 594 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 48 पैसे की नरमी के साथ 20 रुपये हुआ।

मंडल रेलवे अस्पताल, भावनगर में विश्व किडनी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

(जीएनएस)। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन एवं मंडल रेलवे अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार की देखरेख में आज मंडल रेलवे अस्पताल, भावनगर में विश्व किडनी दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किडनी से संबंधित रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके प्रारंभिक लक्षणों की पहचान करना तथा समय पर उपचार के महत्व को समझाना था।

इस अवसर पर अस्पताल के कर्मचारियों एवं मरीजों को किडनी स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम के अंतर्गत किडनी रोगों की

रोकथाम, समय पर जांच और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के बारे में विस्तार से बताया गया।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण नर्सिंग अधीक्षक (BVP) श्री श्रवणसिंह राजपुरोहित द्वारा दिया गया जागरूकता व्याख्यान रहा। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि किडनी हमारे शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जो रक्त को शुद्ध करने, शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने तथा पानी और खनिजों के संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है।

उन्होंने किडनी रोगों के प्रमुख कारणों के रूप में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, असंतुलित आहार, धूम्रपान, अत्यधिक दर्दनिवारक दवाओं का सेवन तथा अस्वस्थ जीवनशैली को जिम्मेदार बताया। साथ ही उन्होंने किडनी रोगों के प्रारंभिक लक्षणों जैसे शरीर में सूजन, अत्यधिक थकान, पेशाब में परिवर्तन, भूख में कमी तथा कमजोरी आदि के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी।

श्री राजपुरोहित ने किडनी को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेने, नियमित व्यायाम करने, रक्तचाप और मधुमेह को नियंत्रित रखने तथा समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि किडनी रोगों की समय पर पहचान और उपचार से गंभीर जटिलताओं से बचा जा सकता है।

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी कर्मचारियों और मरीजों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा किडनी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया।

"भावनगर मंडल के कर्मचारियों ने दिखाई ईमानदारी : ट्रेन में छूटा महिला यात्री का आईफोन सुरक्षित लौटाया"

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के कर्मचारियों ने अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हुए ट्रेन में छूटा एक यात्री का मोबाइल फोन सुरक्षित रूप से वापस लौटाकर सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 10 मार्च 2026 को गाड़ी संख्या 22963 बांद्रा–भावनगर साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कोच संख्या B5 में यात्रा कर रही श्रीमती सुरेखाबेन (उम्र 67 वर्ष) अपना आईफोन ट्रेन में ही भूल गई थीं। यह मोबाइल फोन ट्रेन में

ड्यूटी पर कार्यरत लिनेन सुपरवाइजर श्री शैलेश बारिया को मिला। उन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए मोबाइल को सुरक्षित रखा। इसके बाद दिनांक 11 मार्च 2026 (बुधवार) को गाड़ी संख्या 12972 भावनगर–बांद्रा एक्सप्रेस में ट्रेन कैप्टन श्री विजय कुमार पंड्या (CTI, BVC) की उपस्थिति में उक्त मोबाइल फोन संबंधित यात्री को सकुशल लौटा दिया गया।

इस सराहनीय कार्य के लिए मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने संबंधित कर्मचारियों की ईमानदारी की प्रशंसा करते हुए उन्हें भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया।